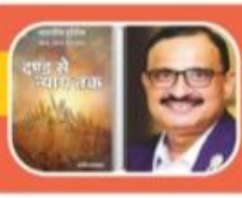

3 प्रवीण कक्कड़ को शिवना कृति सम्मान

5 प्रशासनिक अधिकारी सफल राजनेता

7 दुर्लभ एड्रेनल ब्लैडर ट्यूमर का सफल इलाज

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 37 प्रति सोमवार, 20 जनवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या लक्ष्मीकांत शर्मा की तरह आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जान को हो सकता हैं खतरा?

प्रदेश सरकार को सौरभ शर्मा और उनके परिवार को उपलब्ध करानी चाहिए विशेष सुरक्षा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

मध्यप्रदेश के पूर्व गृह एवं नगरीय निकाय मंत्री भूपेन्द्र सिंह की मुश्किले कम होती नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ भूपेन्द्र सिंह के तार आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा छुपाये गये करोड़ो रुपये और 52 किलो सोने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, अब ईडी और लोकायुक्त की टीम एक के बाद एक भूपेन्द्र सिंह और सौरभ शर्मा के करीबियों के घरों पर छापा मारने की कार्यवाही को अंजाम दे रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर सौरभ शर्मा भूपेन्द्र सिंह के संपर्क कैसे आया, कौन है वो लोग जिनका करोड़ो रुपये की काली कमाई का पैसा सौरभ शर्मा घुमाने का काम कर रहा था। यही नहीं इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या ईडी और लोकायुक्त की टीम जनता और मीडिया के सामने पूरी सही जानकारी रख रही है कि या फिर अभी भी कुछ बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन और नेताओं सहित आईएएस अफसरों के नाम छुपाये जा रहे है। चर्चा जो भी हो लेकिन एक बात तो तय है कि सौरभ शर्मा के ऊपर हो रही छापेमार की इस कार्रवाई ने मध्यप्रदेश के काली करतूत करने वाले नौकरशाह और मंत्रियों के दांत खट्टे कर दिये है।

सौरभ शर्मा को उपलब्ध करवाना चाहिए विशेष सुरक्षा

आरटीओ आरक्षक और इस पूरे मामले का मुख्य सरगना रहा सौरभ शर्मा यदि अपने आपको लोकायुक्त के खिलाफ सरेंडर करता है तो प्रदेश सरकार को सबसे पहले सौरभ शर्मा की जान की सुरक्षा की चिंता करना होगी। क्योंकि सौरभ शर्मा ही वह सूत्र है जो प्रदेश के अन्य नेताओं और अफसरों के नाम अपने बयान में खोल सकता है। ऐसे में एक बात का भय भी है कि कहीं मुख्य आरोपी और इस पूरे मामले के संरक्षक रहे आला मंत्री सौरभ की जान के दुश्मन न बन जाये और सौरभ शर्मा को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाये। जाहिर है कि इससे पहले मध्यप्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिसमें मुख्य आरोपी को कुछ दिन में ही किसी न किसी कारणवश गायब कर दिया गया या तो फिर उसकी मौत हो गई।

लक्ष्मीकांत शर्मा सबसे बड़ा उदाहरण है

पूर्व मंत्री स्व. लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापमं घोटाले के सबसे बड़े गवाह थे। लक्ष्मीकांत शर्मा को इस पूरे मामले की हर जड़ की जानकारी थी। यही वजह है कि पहले पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव की मृत्यु हुई और उनसे पहले उनके ही बेटे ने अपने आवास में फांसी लगाकर जान दे दी। (शेष पेज 6 पर)

सेकेंड स्टोरी

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बंदूक के ट्रिगर बन गये आदिवासी नेता कवासी लखमा

(विस्तृत पेज 2 पर)

प्राकृतिक संपदा की खूबसूरती वाले राज्य को लगी गृहमंत्री विजय शर्मा की नजर

प्रदेश की पुलिस हुई निरंकुश, कांग्रेस राज के दौरान दागदार आईपीएस अफसरों को गृहमंत्री का संरक्षण

-विजया पाठक

आज छत्तीसगढ़ राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, उसका एक कारण है प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि आज अखबार की ज्यादातर खबरें क्राइम पर आधारित ही दिखाई देती हैं। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की हालत के कारण गृहमंत्री विजय शर्मा हैं, कहते हैं सांप को दूध पिलाने पर भी वो डसता जरूर है वैसे ही कांग्रेस के रावणराज के दौरान प्रदेश में हाहाकार मचाने वाले आईपीएस अफसरों को गृहमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। कभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण और खिलखिलाता छत्तीसगढ़ को पिछले

कुछ समय से न जाने किसकी नजर लग गई है। पिछले पांच सालों में जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य की धन संपदाओं को पूरी तरह से खोखला कर दिया।

उदासीन गृहमंत्री के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई राज्य की कानून व्यवस्था

राज्य के पत्रकार मुकेश चंद्राकार की मौत ने राज्य की कानून व्यवस्थाओं पर फिर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। वर्तमान में भाजपा सरकार के गृहमंत्री विजय शर्मा के उदासीन रवैये के चलते राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज गृहमंत्री विजय शर्मा ने पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर विजय शर्मा से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो उन्हें खुद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात करके अपने पोर्टफोलियों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। लेकिन वे पूरी तरह से मूकदर्शक बने बैठे हुये हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। लोग खौफ में हैं, भ्रष्टाचार सहित आपराधिक मामले अपने शिखर पर है। दिन प्रतिदिन राज्य में अलग-अलग कानूनी वारदातें हो रही हैं, जिससे पूरे देश में छत्तीसगढ़ की एक नकारात्मक छवि बन रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार राज्य के अंदर इंसान गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बंदूक के ट्रिगर बन गये आदिवासी नेता कवासी लखमा

लखमा के साथ बघेल एंड कंपनी ने किया विश्वासघात, अब लखमा बढ़ा सकते हैं बघेल की मुश्किलें

-विजया पाठक

प्रदेश सरकार से सत्ता खोने के बाद भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री के तौर पर गले तक भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाने वाले भूपेश बघेल के काले कारनामों के चिट्ठे खुलना आरंभ हो गये हैं। पिछले दिनों बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे आदिवासी नेता कवासी लखमा के ऊपर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान लखमा ने जो बयान दिये हैं उससे साफ पता चलता है कि राज्य में बघेल और उसके करीबियों ने प्रदेश को खोखला करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज लखमा ईडी की कस्टडी में हैं और बघेल पर घेराबंदी करने की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही बघेल के खिलाफ मिले सबूतों की चार्जशीट पेश करते हुये बघेल की गिरफ्तारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय आदिवासी नेता और बस्तर से छह बार के विधायक रहे कवासी लखमा को ईडी ने भूपेश सरकार के वक्त के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इस चर्चित शराब घोटाले में दो हजार करोड़ से अधिक के काले कारोबार का आरोप ईडी ने अदालत में लगाया है, और इस मामले में प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज अफसर और कारोबारी पहले से गिरफ्तार हैं।

बघेल और उसके साथियों ने किया लखमा के साथ विश्वासघात

कवासी लखमा भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे और आबकारी विभाग की फाइलों पर वे बिना पढ़े दस्तखत करते थे क्योंकि वे पढ़ना नहीं जानते, जाहिर तौर पर लिखना भी नहीं जानते और सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं। ऐसे कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या सोचकर या बहुत सोचकर आबकारी मंत्री बनाया था और एक अनपढ़ आदिवासी उस कार्यकाल के लिए अब ईडी की हिरासत में है और गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचना महज वक्त की बात है। ईडी ने अदालत को बताया है कि पहले जिन बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कवासी लखमा को हर महीने दो करोड़ रूपए देने का बयान दिया है और लखमा ने इसी रकम में से परिवार का एक बड़ा सा घर बनवाया है और सुकमा में कांग्रेस भवन भी। कांग्रेस भवन का हिसाब कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कभी चुनाव न हारने वाला यह आदिवासी विधायक ईडी के जाल में फंस चुका है और इसे लेकर लोगों के मन में रंज भी है।

चार्जशीट पर किसी को हैरानी नहीं

दरअसल छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से जानने वाले लोगों के बीच दो हजार करोड़ के शराब घोटाले की चार्जशीट पर किसी को हैरानी नहीं है। प्रदेश में शराब के धंधे और तौर-तरीके को लाखों लोग जानते थे, उन्हें यह हैरानी जरूर हो सकती है कि ईडी कुल दो हजार करोड़ के घोटाले का केस बना पाई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक शराब घोटाले में हुई है, उनमें से किसी की भी मासूमियत का कोई धोखा किसी को नहीं है और सबको यह पता है कि ये लोग पांच बरस किस तरह से आबकारी विभाग चला रहे थे। लोगों को यह भी उतनी ही अच्छी तरह मालूम था कि कवासी लखमा लिखना-पढ़ना नहीं जानते, वे सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में आबकारी जैसा विभाग उन्हें देना और फिर इतना बड़ा शराब घोटाला होना, इनमें कुछ भी मासूम नहीं था।

कवासी लखमा को ईडी ने किया सलाखों के पीछे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि लखमा को रायपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 21 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। हालांकि, लखमा ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने लखमा को पूछताछ के लिए पचपेड़ी नाका क्षेत्र स्थित अपने कार्यालय बुलाया था, जहां उन्हें दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि ईडी ने लखमा को रायपुर की विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में पेश करते हुए उनकी 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया। पांडे के मुताबिक, अदालत ने लखमा को 21 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले लखमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "(उनके परिसरों पर ईडी के) छापे के दौरान न तो कोई दस्तावेज मिला और न ही एक पैसा। मुझे झूठे मामले में जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय "एक गरीब आदिवासी" और आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लखमा ने दावा किया, "चूंकि, राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और वे मुझे चुनाव से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ यह कार्रवाई की है।" छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भूपेश बघेल ने ईडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई

भूपेश बघेल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई है। ईडी केंद्र में सत्ता में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है।" इससे पहले, ईडी ने एक बयान में दावा किया था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान आबकारी मंत्री रहे लखमा शराब 'घोटाले' में अपराध की आय के मुख्य प्राप्तकर्ता थे। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि लखमा को "शराब घोटाले से अर्जित अपराध की आय से मासिक आधार पर नकद में बड़ी रकम" हासिल होती थी। ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था। कोंटा (सुकमा जिला) से छह बार के विधायक लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे।

सरकारी खजाने को भारी नुकसान

जांच एजेंसी ने दावा किया था, "छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में अपराध से अर्जित 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की आय गई।" ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। लखमा की रिमांड अर्जी में ईडी ने कहा कि पूछताछ में कई लोगों ने कांग्रेस नेता का नाम अपराध की आय से मासिक भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में लिया है। जांच एजेंसी ने कहा, "लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे और विभाग पर उनका पूरा नियंत्रण था। उन्हें अपने विभाग में अनियमितताओं के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वह अपनी भूमिका के लिए अपराध से बड़ी मात्रा में कमाई कर रहे थे।" ईडी ने कहा कि लखमा ने नीति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण राज्य में एफएस-10ए लाइसेंस (जिनके धारकों को विदेशी शराब की आपूर्ति के लिए निविदा दी गई थी) की शुरुआत हुई। जांच एजेंसी ने कहा कि लखमा ने सिंडिकेट के एक अभिन्न अंग के रूप में काम किया और इसमें शामिल लोगों के निर्देश के अनुसार प्रक्रियाओं को संचालित करके सिंडिकेट की सक्रिय रूप से सहायता की।

प्राकृतिक संपदा की खूबसूरती वाले राज्य को लगी गृहमंत्री विजय शर्मा की नजर

(पेज 1 से जारी)

सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हैं। अस्पताल में अनैतिक घटना हो जाना गृहमंत्री की कमजोरी का परिणाम है। यही नहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी तक सुरक्षित नहीं हैं। समय के साथ राज्य अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और आश्चर्य यह होता है कि अभी तक गृहमंत्री विजय शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आपराधिक घटनाओं के कारण बढ़ती जा रही संख्या

विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार पिछले सात महीने में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्यायें। चाकूबाजी, लूट, डकैती, चेन स्नेचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि यह तो सिर्फ वह आंकड़ें हैं जो सरकारी दस्तावेज में शामिल हैं। ऐसे और न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम बड़ी ही सुझबूझ के साथ दिया गया है जिन पर अभी तक कोई कार्रवाही नहीं होती दिखाई दे रही है। जाहिर है कि गृहमंत्री विजय शर्मा खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरह के घटनाएं बंद हो, क्योंकि वे आपराधिक घटनाओं के तबे पर सियासी रोटियां सेंकने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते।

गृहमंत्री का नहीं है कोई नियंत्रण

राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा का खुद कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि अपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह वे घटनाएं हैं जिनके बारे में विचार करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं पोस्ट लिख रही हूं उस समय मेरे दिमाग में जगदलपुर शहर में हुई तीन बड़ी घटनाओं का स्मरण आता है। दिल दहला देने वाली यह घटनाएं पांच दिन में अंजाम दी गई। यही नहीं दीपावली के तीन दिनों में राजधानी रायपुर में ही 07 हत्यायें हुई। राजधानी से लगे भिलाई, दुर्ग जिले में 04 हत्यायें हुई हैं। तीन से चार दिनों में राजधानी क्षेत्र में रायपुर भिलाई में कुल 11 हत्यायें हुई हैं।

बिहार-यूपी जैसे हालात बनते जा रहे हैं

छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बिहार, यूपी से भी ज्यादा डरावनी हो गयी है। गृहमंत्री विजय शर्मा राज्य को मणिपुर की तरह जलते हुये देखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश में पहली बार जातीय आधार पर संघर्ष होता देखा गया। राजधानी के सकरी गांव में दंगा हो गया, एक घर में आग लगा दी गई, वाहनों को जला दिया गया, यदि परिवार वाले गांव छोड़कर नहीं जाते तो 11 सदस्य का पूरा परिवार घर में जिंदा जल गया होता। कुल मिलाकर सभी केवल इस बात को लेकर आशांन्वित हैं कि राज्य में खस्ताहाल हो चुकी कानून व्यवस्था को दूरस्त कब किया जायेगा।

गृहमंत्री बनते ही दो महीने में हुए 54 नक्सली हमले

विजय शर्मा के गृहमंत्री बनने के बाद राज्य में एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य में 54 नक्सली घटनाएं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबल के सात जवान तथा एक 'गोपनीय सैनिक' शहीद हुआ है। इस दौरान 53 जवान घायल हुए तथा आठ नक्सली भी मारे गए हैं। नक्सली घटनाओं में सुकमा जिले में चार जवान शहीद हुए हैं तथा 25 जवान घायल हुए हैं। वहीं बीजापुर जिले में दो जवान शहीद हुए हैं तथा 21 जवान घायल हुए हैं। जिले में मुठभेड़ में चार नक्सली भी मारे गए हैं।

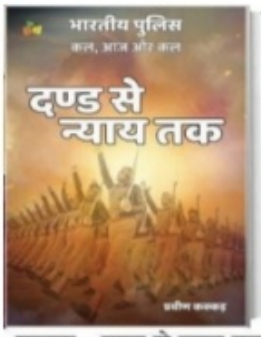

पुस्तक - दण्ड से न्याय तक

प्रवीण कक्कड़

प्रवीण कक्कड़ को मिलेगा शिवना कृति सम्मान

शिवना प्रकाशन द्वारा हुई प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा

-संवाददाता

जगत प्रवाह. भोपाल। शिवना प्रकाशन द्वारा प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा की गई। इसमें नए भारतीय कानून पर आधारित पुस्तक ''दंड से न्याय तक'' के लेखक प्रवीण कक्कड़ को शिवना कृति सम्मान देने की घोषणा की गई है। इनकी इस पुस्तक ने काफी कम समय में देशभर में लोकप्रिय होकर अनूठी पहचान बनाई है, वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस पुस्तक में प्रवीण कक्कड़ ने कानून की जटिलताओं को बेहद आसान ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक से आम आदमी भी बीएनएसएस और आईपीसी के अंतर को समझ सकता है। विदित हो कि यह पुस्तक कानूनी छात्रों के साथ ही अधिवक्ताओं और पुलिस विभाग में भी खासी लोकप्रिय है। शिवना प्रकाशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा की गई। शिवना सम्मानों के लिए बनायी गयी चयन समिति के संयोजक, पत्रकार तथा लेखक आकाश माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवना प्रकाशन द्वारा दो सम्मान प्रदान किये जाते हैं- एक 'अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान' जो वर्ष भर में सभी प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित साहित्य की सभी विधाओं की पुस्तकों में से निर्णायकों द्वारा चयनित एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है तथा दूसरा 'शिवना कृति सम्मान' जो वर्ष भर में शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में गुणवत्ता एवं विक्रय के सम्मिलित आधार पर पुस्तक को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इन सम्मानों की घोषणा कथाकार, उपन्यासकार पंकज सुबीर ने ऑनलाइन की। 'अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान' राजपाल एंड संस प्रकाशन से प्रकाशित उपन्यास 'क़िस्साग्राम' के लिए प्रभात रंजन तथा सेतु प्रकाशन से प्रकाशित कहानी संग्रह 'बांग छो' के लिए मनीष वैद्य को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। 'शिवना कृति सम्मान' अकादमिक पुस्तक 'दण्ड से न्याय तक' के लिए लेखक प्रवीण कक्कड़ को प्रदान किया जायेगा। निर्णायक मंडल में अमेरिका निवासी वरिष्ठ लेखक सुधा ओम ढींगरा तथा राष्ट्रपति स्वर्ण कमल सम्मान से सम्मानित लेखक यतीन्द्र मिश्र शामिल थे। आकाश माथुर ने बताया कि शीघ्र ही एक गरिमामय सम्मान समारोह में इन सम्मानित रचनाकारों तथा पूर्व में घोषित नवलेखन पुरस्कार के लेखकों रश्मि कुलश्रेष्ठ तथा शुभ्रा ओझा को सम्मान राशि, शॉल, तथा स्मृति चिह्न प्रदान कर यह सम्मान प्रदान किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे जीरो टॉलरेंस पर अमल

लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध हो रही कड़ी कार्रवाई

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। राज्य में भ्रष्टाचार और गडबड़ी पर जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने कई अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस का परिचय दिया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की है। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बीजापुर में आर.आर. पी.-1 (एल.डब्ल्यू.ई.) योजना के अंतर्गत 54.40 किमी लंबाई के अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन में पाई गई गड़बड़ियों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार/निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क

निर्माण कार्य में गड़बड़ियों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किए जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता बी.एल. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी आर.के. सिन्हा और उप अभियंता जी.एस. कोड़ोपी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर तत्काल लोक निर्माण विभाग को सूचित करने के निर्देश बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के मुख्य अभियंता को दिए हैं।

नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एवं बस्तर मंडल के अधीक्षण अभियंता के साथ विगत 8 जनवरी और 9 जनवरी को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई कमियां पाई गईं। मार्ग के निर्माण कार्य में 29.00 किमी से 32.00 किमी एवं 50/10 तक कुल 4.20 किमी बी.टी. कार्य में अधिकांश जगह सील कोट उखड़ गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 41/2 से 50/10 मार्ग के विभिन्न फर्लांग में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42/10, 43/2, 43/4, 43/8, 44/6, 44/8, 45/4, 45/6, 45/8, 45/10, 46/6, 47/2, 47/10 एवं 50/8 सड़क सतह सिंक पोथोल्स उत्पन्न हो गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 28/4, 30/6 एवं 40/2 में पुल के एप्रोच स्लैब अपर्याप्त मोटाई एवं बिना रिइनफोर्समेंट के बैक फीलिंग मटेरियल के कमजोर कॉम्पेक्शन होने से सेटल्ड हो गया है। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी आर.के. सिन्हा, और उप अभियंता जी.एस. कोड़ोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। लोक निर्माण विभाग ने नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य में निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को गंभीर कदाचार मानते हुए बीजापुर के सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें जारी नोटिस में विभाग ने कहा है कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्हें इस संबंध में अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

गगनई जलाशयः प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का स्वर्ग गगनई जलाशय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों से समृद्ध है। यहां की पहाड़ियां, नदी-नाले और जंगल, प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन्हीं आकर्षणों में से एक है गगनई जलाशय, जो जिला मुख्यालय गौरेला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलाशय प्रकृति की गोद में स्थित एक ऐसा स्थान है, जहां पर्यटक नौकायन, पिकनिक और साहसिक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं।

गगनई जलाशय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह स्थान हर किसी को सुकून प्रदान करता है। जलाशय का मुख्य आकर्षण है नौकायन (बोटिंग), जो पर्यटकों को खास अनुभव प्रदान करता है। इसके साथ ही यहाँ का सनसेट पॉइंट बेहद लोकप्रिय है। झील में डूबते सूरज की लालिमा और चारों ओर पहाड़ों का दृश्य यहां आने वाले हर पर्यटक का दिल जीत लेता है। झील का यह मनोरम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने अपनी कलाकृति को निखार कर यहां सजाया हो। गगनई जलाशय में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। वन विभाग द्वारा बनाए गए सर्व-सुविधायुक्त कमरे और कैंटीन मुख्य आकर्षण हैं। पर्यटक अपने परिवार के साथ यहां रुककर शांत और सुकून भरे पलों का आनंद ले सकते हैं।

गगनई जलाशय सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। नाइट कैम्पिंग, ट्रेकिंग, और पक्षीदर्शन जैसी साहसिक गतिविधियों का भी यहां आयोजन होता है। पर्यटकों के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए नवाचार कैंप इस स्थान की खासियत को और बढ़ाते हैं। यह नेचर कैंप भालुओं के आवास वाले जंगल के करीब स्थित है। यहां वन विभाग द्वारा पर्यावरण चेतना केंद्र स्थापित किया गया है, जो भालुओं के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। कभी-कभी भालुओं के दर्शन भी पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं।

गगनई नेचर कैंप पूरे साल पर्यटकों से गुलजार रहता है। स्थानीय लोग और बाहरी पर्यटक इसे पिकनिक के लिए उपयुक्त स्थान मानते हैं। शांत जलवायु, मनोरम दृश्य, और सुविधाओं के कारण यह राज्य के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। गगनई जलाशय केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, रोमांच और सुकून का संगम है। यह स्थान उन सभी के लिए आदर्श है, जो प्रकृति के करीब आकर शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं।

इन्वेस्टमेंट तब आता है जब विश्वास का माहौल मिले

(पेज 5 से जारी)

केवल भाषणबाजी करने से और विज्ञापन व मीडिया इवेंट्स से निवेश नहीं आता। पिछले 05 सालों से प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही हैं लेकिन भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 0.3 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट राज्य को मिला है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सवाल है कि पिछले 18 वर्षों में प्रदेश में हुए ऐसे निवेशक सम्मेलन में आए 6,500 प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव धरातल पर उतरे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आए दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के वादों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निजी क्षेत्र से आने वाला यह निवेश तो दूर की बात है, केंद्र सरकार से प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले पैसे को ही अब तक राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकी है। मध्यप्रदेश को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 37,652 करोड़ रुपया मिलने थे लेकिन अब तक सिर्फ 16,194 करोड़ रुपये ही मिले हैं। मध्य प्रदेश में आए तमाम निवेशकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वास की एक नयी परंपरा बने, हम इस बात का स्वागत करते हैं। 08 दिसंबर 2003 से लेकर अब तक करीब 22 साल में प्रदेश में लगभग 23 साल भाजपा का शासन रहा और 15 महीने (17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक) कांग्रेस सत्ता में रही। इस दौरान मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था।

सम्पादकीय

फिल्म अभिनेताओ के ऊपर जानलेवा हमले चिंता का विषय

अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले ने सभी को सकते में डाल दिया है। घर में घुसकर उन पर किया गया हमला कोई सामान्य घटना नहीं है। मुंबई में अगर इस स्तर की बड़ी हस्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम शहरी किस तरह खुद को महफूज समझेगा? यहां कुछ नेताओं और अभिनेताओं को कुख्यात अपराधियों ने जिस तरह निशाने पर लिया है, उससे मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। यह हैरत की बात है कि बांद्रा स्थित इमारत की बारहवीं मंजिल पर अभिनेता के घर में देर रात हमलावर घुसा और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर आसानी से भाग भी गया। राहत की बात बस यह है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं। हकीकत विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी, मगर इस घटना ने देश की आर्थिक राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। बांद्रा में कई जानी-मानी और फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां रहती हैं। बावजूद इसके वहां की सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि एक इमारत में घुस कर हमला करने के बाद आरोपी व्यक्ति भाग भी गया। कुछ समय पहले इसी इलाके में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच सलमान खान को भी धमकियां मिलने की खबरें आईं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह दावा है कि मुंबई देश का सबसे सुरक्षित महानगर है। मुंबई पुलिस अपने कामकाज को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता वाला बताती है। सवाल है कि इसके बावजूद मुंबई में मशहूर हस्तियों के सामने इस तरह के जोखिम क्यों पैदा हो रहे हैं। कोई हमलावर बेखौफ अपना काम करके कैसे निकल जाता है? सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। अगर मुंबई को एक असुरक्षित होता शहर बताया जा रहा है, तो यह बेवजह नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर किन कारणों से मुंबई दिनोंदिन असुरक्षित होती जा रही है। सैफ अली खान पर हमला एक आम उदाहरण नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह साफ है कि अगर मुंबई में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकारी दावों के अनुरूप जमीनी स्तर पर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो सरकार से लेकर वहां की पुलिस तक की कार्यकुशलता पर सवाल उठेंगे।

सियासी गहमागहमी

जिला अध्यक्ष बनाने में चली वीडी शर्मा की

मध्यप्रदेश भाजपा ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। जिलाध्यक्षों के नाम घोषित होने के पहले से ही इस बात के कयास लगाये जा रहे थे प्रदेश में जिलाध्यक्षों का चयन प्रदेश स्तर के नेता आपस में मिलकर कर लेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भाजपा नेताओं में आपसी समांजस्य ठीक नहीं बैठा और आपसी खींचतान के बाद पूरा मामला दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के नेताओं द्वारा किये गये हस्तक्षेप के बाद भाजपा ने जिलाध्यक्ष घोषित किये। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जिलाध्यक्षों के नाम में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की चली यही कारण है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश से अधिक वीडी शर्मा के चहेतों के नामों पर मुहर लगी।

कटारे ने भूपेन्द्र सिंह को दिखाया आईना

कांग्रेस के युवा विधायक और नेता हेमंत कटारे ने पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को आईना दिखा दिया है। हेमंत कटारे ने भूपेन्द्र सिंह को चोरी ऊपर से सीनाजोरी की उलाहना देते हुये कटाक्ष किया कि यह दोहरी राजनीतिक मंशा है। कटारे ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह एक तरफ आपकी हस्ताक्षरित नोटशीट पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति का आदेश साफ-साफ दर्ज है और दूसरी तरफ आप बयान दे रहे हैं कि आपने ऐसी कोई नोटशीट बनाई ही नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि भूपेन्द्र सिंह कटारे के इस बयान का अब क्या जबाव देते हैं और खुद को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

"लहसुन कभी 40 था, आज 400!"

बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट - कुंभकरण की नींद सो रही सरकार!

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

"मैं जब तक जिंदा हूं
तब तक जहाँ भी किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर अगर आक्रमण होगा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई से भिड़ा हो, दलित हो

वहाँ पर आपको उनकी रक्षा करता राहुल गांधी मिलेगा"

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

पहले सफल प्रशासनिक अधिकारी बने, अब सफल राजनेता के रूप में आगे बढ़ रहे ओपी चौधरी

समता पाठक/जगत प्रवाह

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी जन्म 02 जून 1981 को हुआ है। वे रायगढ़ जिले की खरसिया ब्लॉक के ग्राम बायंग के रहने वाले हैं। इनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। जब ओमप्रकाश चौधरी मात्र 8 साल के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पिता की मौत के बाद उनकी माता कौशल्या ने पेंशन की आय से उनको पाला। ओपी चौधरी ने पांचवीं तक की शिक्षा अपने गांव बायंग के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। फिर आठवी तक की शिक्षा जैमुरी से की। बारहवीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद उन्होंने पीईटी उत्तीर्ण की पर वह इंजीनियर ना बनकर आईएएस ही बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भिलाई से बीएससी किया। ओपी चौधरी ने यूपीएससी की तैयारी कर अपने पहले ही प्रयास में एग्जाम क्रैक कर लिया। वह मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही आईएएस अफसर बन गए थे। ओपी चौधरी 2005 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर थे। पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के तौर पर 2006 में कोरबा में हुई। इसके बाद 2007 में उन्हें रायपुर में एसडीएम बनाया गया। 2007 में उन्हें जांजगीर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया। वे राजधानी रायपुर के नगर निगम कमिश्नर भी रहे। साल 2011 में उन्हें दंतेवाड़ा में कलेक्टर के तौर पर पदस्थ किया गया। रायपुर कलेक्टर भी ओपी चौधरी रहे। दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा के साथ आवासीय स्कूल की शुरुआत की। चौधरी ने गीदम ब्लॉक में स्थित एक छोटे से गांव, जावंगा को 2011 में शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया। चौधरी ने जिले में लाइवलीहुड कॉलेज की भी शुरुआत की, जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया गया। 2011-12 में बेहतर काम के लिए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।

राजनीतिक जीवन

पिछला विधानसभा चुनाव ओपी चौधरी ने खरसिया विधानसभा से लड़ा था। तब कांग्रेस के प्रत्याशी उमेश पटेल ने ओपी चौधरी को 16,967 मतों से हराया था। उमेश पटेल को 94,201 वोट मिले थे, वहीं ओपी चौधरी को 77,234 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था। हार के बाद भी ओपी चौधरी लगातार सक्रिय रहे थे। वे राज्य के प्रमुख मुद्दों को उठाने के साथ ही युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग भी करते थे। उनकी सक्रियता और कोरबा में कोयला चोरी का मुद्दा उठाने व सोशल मीडिया में वीडियो डालने पर उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज हुआ था। वे लगातार कांग्रेस की नीतियों पर हमला करते हुए सक्रिय रहते थे। जिसके चलते उन्हें चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश भाजपा महामंत्री का पद दिया गया था।

रायगढ़ जिले की रायगढ़ विधानसभा इकलौती ऐसी सीट है जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की है। खरसिया, लैलूंगा, धरमजयगढ़ व पड़ोसी जिले की सारंगढ़ विधानसभा में कांग्रेस जीती है। रायगढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी को 129134 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश नायक को 64691 वोट मिले। भाजपा संगठन ने जिले की अन्य सीटों की जगह इकलौती रायगढ़ विधानसभा में ही फोकस किया था। यही वजह है कि जिले की अन्य विधानसभाओं में भाजपा हार गई और इकलौती रायगढ़ विधानसभा जीती। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी रायगढ़ में ओपी चौधरी के पक्ष में रैली निकाली। साथ ही उन्होंने ओपी को चुनाव जितवाने की अपील करते हुए कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाकर भेजिए मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। जिसका असर हुआ। महतारी वंदन योजना का भी असर हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महतारी वंदन योजना के फॉर्म घर-घर जाकर भरवाए। युवा चेहरा लोगों को पसंद आया। ओपी ने अपनी प्राथमिकता में युवाओं को रखा था। इंफ्रास्टक्चर विकास व शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी का वादा काम आया।

इन्वेस्टमेंट तब आता है जब विश्वास का माहौल मिले

बड़ा सवालः इन्वेस्टर्स मीट्स से क्या मिला मध्यप्रदेश को?

कमलनाथ

(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

इवेंटबाजी छोड़कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बार-बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भी 22 वर्ष तक इसी तरह के दावे करते रहे। इन दावों की हकीकत प्रदेश की जनता के सामने है। प्रदेश में 'पैसा दो काम लो' का सिद्धांत भाजपा ने लागू कर रखा है। इन हालात में निवेश की घोषणा तो की जा सकती है लेकिन वास्तविक निवेश जो कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने वाला हो, उसे लाना मुश्किल है। इसलिए मुख्यमंत्री को मेरी सलाह है कि हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंटबाजी छोड़कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, जिससे जनता और निवेशक दोनों का भरोसा प्रदेश के ऊपर बने और प्रदेश में तरक्की और खुशहाली आए। मैंने अपनी 15 माह की सरकार में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिले इसके लिये कई प्रावधान किये। मैंने हमारी सरकार बनते ही उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70 प्रतिशत प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया। युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार मिले इसके लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय किये। 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही यह किसी से छिपी नहीं। युवा हाथों में डिग्री लेकर नौकरी के लिये दर-दर भटकते रहे। हमने अपनी 15 माह की सरकार में इसी पहचान को बदलने का काम किया, विश्वास का माहौल बनाने का काम किया। साल 2019 में 773.29 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए दी गई, जो साल 2018 के मुकाबले 67 फीसदी ज्यादा है। उद्योगों के लिए 7365 करोड़ का निवेश हुआ, जो कि साल 2018 के मुकाबले 52 फीसदी ज्यादा है। 2019 का साल भले ही केंद्र के लिए आर्थिक मंदी के दौर से उबरने से जूझते हुए निकल गया हो लेकिन प्रदेश में औद्योगिक निवेश की सरकारी कोशिशें असरदार साबित हुईं। सरकारी आंकड़ों से दावा किया गया था कि प्रदेश में हमारी सरकार के उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिशों के कारण 32 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश में एक साल पूरे करने में उद्योग में निवेश के लिए 250 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हाथ आगे बढ़ाया था।

प्रदेश की औद्योगिक नीति पिछली भाजपा सरकारों के 20 वर्षों में इन्वेस्टर्स मीट्स के नाम से शुरू और खत्म हो गई। आंकड़े गवाह हैं कि इन वर्षों में मध्यप्रदेश औद्योगिक राज्य के रूप में अपने आप को विकसित नही कर पाया है। प्रदेश में सेक्टोरियल डेव्लपमेंट बेस्ड इंवेस्टमेंट उद्योग जगत से नहीं आया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि प्रदेश के नेताओं पर उद्योगपति बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इंवेस्टमेंट के लिए सरकार और औद्योगिक घरानों के बीच में एक विश्वास का संबंध होता है क्योंकि जो औद्योगिक घराने अपना कमिटमेंट कर निवेश करती है उसको फायदा भी मिलना चाहिए। वहीं राज्य को औद्योगिक इंवेस्टमेंट से रोजगार (स्किल डेव्लपमेंट), प्रदेश को आय, स्थानियों के लिए डायरेक्ट-इनडायरेक्ट आय का जरिया बनते हैं।

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के समय भी इन्वेस्टर्स मीट्स के काफी आयोजन हुए। शिवराज जी के समय में लगभग एक दर्जन इन्वेस्टर्स मीट्स हुईं। उसी परिपाटी पर अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चल रहे हैं। पिछले एक साल में मोहन यादव भी कई इन्वेस्टर्स मीट कर चुके हैं। फरवरी 2025 में भी भोपाल में एक इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन इन्वेस्टर्स मीट से प्रदेश को हासिल क्या हो रहा है? सरकार दावा तो खूब करती हैं कि इन्वेस्टर्स मीट से हजारों करोड़ का निवेश आयेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हकीकत में जो हासिल हो रहा है वह नहीं बताया जाता है। सिर्फ कागजों पर आंकड़े बता देने से निवेश नहीं आता है। सरकार का दावा है कि अब तक तीन लाख 75 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे लगभग 84 हजार रोजगार के सृजन की संभावना है। पिछले 08 माह में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं मुंबई, कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड-शो हुए। सरकार का मानना है कि इनमें विभिन्न सेक्टर्स में 02 लाख 76 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 03 लाख 28 हजार 670 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टर्स समिट एक नाटक-नौटंकी है, इससे मध्यप्रदेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन्वेस्टमेंट तब आता है जब विश्वास का माहौल मिले। (शेष पेज 6 पर)

क्या सफल हुई हैं इन्वेस्टर समिट?

इन्वेस्टर समिट को लेकर इससे पहले मध्य प्रदेश में हुए कार्यक्रमों पर नजर डालें तो नतीजे उतने बेहतर नहीं आए हैं, जितने तत्कालीन सरकार की ओर से दावे किए गए थे। 2012 और 2014 में शिवराज सरकार के दौरान हुई ग्लोबल इंवेस्टर समिट के आयोजन और नतीजों को देखें तो अक्टूबर 2012 में इंदौर में हुई ग्लोबल इंवेस्टर समिट में सहारा ग्रुप ने 20 हजार करोड़ के निवेश की डील की थी। ये डील डेयरी और एग्रो सेक्टर प्रोजेक्ट्स में की गई थी, लेकिन ये भी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी जीआईएस में महिंद्रा-एंड-महिंद्रा ने 3000 करोड़ की लागत से एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का दावा किया था। बाद में कंपनी ने एमओयू साइन करने से इनकार कर दिया। सूर्या ग्लोबल ने सीमेंट सेक्टर और सूर्यचक्र ग्रुप ने पॉवर सेक्टर में निवेश की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन माइनिंग परमिशन में देरी के चलते प्रोजेक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जबकि 2014 में हुई जीआईएस में जेपी ग्रुप ने 35 हजार करोड़ के निवेश की बात की थी, तब जेपी ग्रुप की ओर से माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने का दावा किया गया था। पहले फेज में जेपी एसोसिएट्स की ओर से 18 हजार करोड़ निवेश की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट भी परवान नहीं चढ़ सका। 22-23 अक्टूबर 2016 को इंदौर में ही जीआईएस के आयोजन से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ने अमेरिका का दौरा किया था लेकिन इस समिट के बाद के नतीजे भी उतने बेहतर नहीं आए जितना दावा सरकार की ओर से किया गया था।

हमारी सरकार ने पांच सितारा इन्वेस्टर्स मीट की परिपाटी को खत्म किया

हमारी सरकार ने पांच सितारा इन्वेस्टर्स मीट की परिपाटी को खत्म करते हुए मिंटो हॉल में उद्योगपतियों की राउंड टेबल बैठक बगैर किसी ताम्झाम के आयोजित की। उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा कर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों पर बात की और उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर वे सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, उस पर चर्चा की और सुझाव लिए। पिछली सरकार के समय पांच सितारा परंपरा के अनुरूप इन्वेस्टर्स मीट होती थीं, निवेश लाने के नाम पर ताम्झाम और प्रचार पर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते थे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि वह इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर फिजूलखर्ची नहीं की। पूर्व सरकारों में सिर्फ करोड़ों रुपए के निवेश पर खर्च किए। इसके बाद उद्योग लगे ही नहीं।

कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन के सार्थक उपाय

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अकसर कुंभ जैसे मेले और बड़े धार्मिक उत्सवों में आकस्मिक दुर्घटनाएं देखने में आती रही हैं. हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मचने से छह लोगों के प्राण चले गए और 150 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटनाएं इसलिए घटती रही हैं, क्योंकि मेला प्रबंधन पूर्व से दुर्घटना न घटे इस दृष्टि से सतर्क दिखाई नहीं देते हैं। किंतु प्रयागराज में होने वाले कुंभ में इस बार देखा जा रहा है कि कोई दुर्घटना न घटे इस नजरिये से अनेक तरह के भौतिक और तकनीकि प्रबंध किए गए हैं। समय के साथ ये बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ में अस्थाई रूप से निर्मित की गई 'कुंभनगरी' में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 मार्च तक चलने वाले इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा संबंधी निगरानी के उपाय व्यापक स्तर पर कृत्रिम बुद्धि से संचालित उपकरण करने लगे हैं। इस हेतु कुंभनगरी का पूर्णतः डिजिटलीकरण कर दिया है। प्रत्येक 12 साल में प्रयाग में गंगा-यमुना और अदृष्य सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ आयोजित होता है। 45 दिन चलने वाले इस कुंभ में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। 2013 में 20 करोड़ से ज्यादा यात्री प्रयाग पहुंचे थे। इस बार दोगुने से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान इसलिए है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का भी कायाकल्प हुआ है। साथ ही आवागमन के साधन बढ़े हैं। अतएव 4 तहसील और 67 ग्रामों की 6000 हेक्टेयर भूमि पर मेले में यात्रियों के लिए समुचित प्रबंध करके योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मिसाल प्रस्तुत की है, जो अनुकरणीय है।

लोगों को आवाजाही में असुविधा न हो? इसलिए मेला प्राधिकरण और गूगल के बीच हुए समझौते के अंतर्गत आवागमन मानचित्र (नेविगेशन मैप) की सुविधा मोबाइल व अन्य संचार उपकरणों पर दी गई है। इस सुविधा से यात्री गंतव्य की स्थिति और दिशा हासिल कर सकते हैं। इस मानचित्र में मेले की धार्मिक महिमा से जुड़े नदी-घाट, मंदिर, अखाड़े, संतों के डेरे, ठहरने के स्थल, होटल और खान-पान संबंधी भोजनालयों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा पर्व स्नान माना है। अतएव इस दिन छह से दस करोड़ लोग गंगा में स्नान करने का अनुमान है। बांकी पांच पर्वों में 2 से 8 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आ सकते हैं। वैसे तो सुरक्षा के लिए 37000 पुलिस और विभिन्न बलों के जवान तैनात रहेंगे, लेकिन इतने लोगों पर इन जवानों द्वारा निगाह रखना आसान नहीं है, इसलिए समूची कुंभनगरी में कृत्रिम बुद्धि आधारित कैमरे लगा दिए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर लगे इन 2400 कैमरों की आंख में एआई लैंस लगे हैं। अतएव ये चेहरे पहचानकर अपराधियों पर नजर रखेंगे। इस नगरी में जगह-जगह डिजिटल और बहुभाषी टच स्क्रीन बोर्ड लगाए गए हैं। जिन पर किसी भी प्रकार की घटना की तत्काल शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। ये सुविधाएं मेले में दिन-रात उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ के इस पर्व पर ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

धरती तो धरती नदी जल में भी नावों की विभाजक पंक्ति (डिवाइडर) बना दी गई है। इस नवाचार से गंगा और यमुना के जलमार्ग पर नावों के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यह अनूठा विभाजक कुछ इस तरह से बना है कि रामसेतु में प्रयोग में लाए गए वायुयुक्त पत्थरों की जगह यहां प्लास्टिक के वर्गाकार क्यूब स्थापित किए गए है। जो तैरते चबूतरे अनुभव होते हैं। इनमें पर्याप्त लचीलापन है, इसलिए भीड़ बढ़ने पर ये फैल जाएंगे और लोग आसानी से संगम पर स्नान करते रहेंगे। इससे श्रद्धालुओं को नौकाएं प्राप्त करने में भी सुविधा रहेगी। आठ हजार से भी ज्यादा नाविकों को यात्रियों से संयम से बात करने और संकट के समय विवेक बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविकों को क्रोध पर नियंत्रण रखने को भी कहा गया है। सुरक्षाकर्मियों को संकट के समय संकेत की भाषा (कोड वर्ड) में बात करने की हिदायत दी गई है। जिससे भगदड़ न मचे। इसी तरह की हिदायतें अग्नि शमन वाहनों के चालकों को दिया गया है। इन्हें आग या अग्नि षब्द का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है, जिससे लोग दहशत में न आए।

कुंभ मेले में इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो कई देषों की आबादी से ज्यादा होते हैं। इस चुनौती को अवसर में बदलकर यह उत्सव निर्बाध चलता रहे इसकी जुम्मेबारी मेला अधिकारी (आईएएस) विजय किरन आनंद को सौंपी गई है। 2019 के कुंभ का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि भीड़ प्रबंधन का प्रषिक्षण किन्हीं विदेशी संस्थानों से लेने की बजाय पूर्व में आयोजित कुंभ मेलों में घटी घटनाओं और उत्तम सुरक्षा व्यवस्थाओं से लिया गया है। यह इसलिए जरूरी था, क्योंकि इतना बड़ा मेला दुनिया में कहीं लगता ही नहीं है। अतएव वहां के लोगों को करोड़ों लोगों की भीड़ का प्रबंध कैसे किया जाए, यह अनुभव ही नहीं है। विशेष पर्वों को अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन अत्यधिक भीड़ रहती है। इसलिए एक साथ समूहों में संगम पर उमड़ने वाली इस भीड़ को डुबकी लगाने के बाद तत्काल वापिस भेजने का प्रबंध किया गया है। यह भीड़ प्रयागराज से अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवानगी डाल दें इस दृष्टि से प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर हर समय 200 से ज्यादा रेलें उपलब्ध रहेंगी। इसी तरह प्रत्येक दस मिनट पर 600 से ज्यादा बसें यात्रियों को भरकर वापसी की तैयारी में खड़ी मिलेंगी। यात्रियों को वापसी के ये प्रबंध इसलिए अहम है, क्योंकि 2013 में प्रयागराज के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई थी। 2013 जैसी स्थिति न बनें इस नजरिये से 60,000 लोगों को रोकने के लिए विशेष क्षेत्र निर्मित किए गए हैं। इन्हें इसी क्षेत्र में लगे डिजीटल बोर्ड पर यात्री सेवाओं की उपलब्ध जानकारियों के साथ रेल और बसों के प्रस्थान की जानकारियां भी मिलती रहेंगी। चिन्हित क्षेत्रों में मिलने वाले इस रियल टाइम डाटा की सुविधा भीड़ की रणनीति से निपटने का उपयुक्त उपाय माना रहा है। मेले के बाहर पार्किंग स्थलों पर चार से पांच लाख लोगों को रोकने के पृथक से प्रबंध किए गए हैं।

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल देखने में आ रहा है। धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूर्व से नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी सजगता मेले के आरंभ होने के पहले से स्पष्ट दिखाई दे रही है। अन्यथा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता था, जिसे वह यदि समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं होने पाते? यह सतर्कता इस बार के महाकुंभ में बरती गई है।

क्या लक्ष्मीकांत शर्मा की तरह आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जान को हो सकता है खतरा?

(पेज 1 से जारी)

यह मामला यही नहीं रूका मुख्य आरोपी ने लक्ष्मीकांत शर्मा को भी नहीं बख्शा। लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के बाद लक्ष्मीकांत को धीरे-धीरे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में सौरभ शर्मा भी कहीं इस तरह किसी वारदात के शिकार न हो इसलिये सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए।

उप नेता प्रतिपक्ष ने घेरा भूपेन्द्र सिंह को

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उप नेता प्रतिपक्ष अटेर विधायक हेमंत कटारे ने इस मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह को घेरा। उन्होंने सौरभ शर्मा की पोस्टिंग कराने के लिए पूर्व परिवहन मंत्री पर केस दर्ज करने की भी मांग की थी। अब भूपेन्द्र सिंह ने हेमंत कटारे को फांसा है। कटारे पर दर्ज रेप केस में उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट बदले जाने के गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में सीएम और डीजीपी को पत्र भी लिखा।पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर दर्ज दुष्कर्म केस में एफएसएल रिपोर्ट बदले जाने की गहराई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव की गई। एफएसएल रिपोर्ट बदले जाने की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

ईडी की लगातार कार्रवाई जारी

पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल की काली कमाई के मामले में जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। काली कमाई को लेकर ईडी ने ग्वालियर में बड़ी रेड की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के करीबी रिश्तेदारों के बिजनेस पार्टनरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार केके अरोरा के घर छापामार कार्रवाई की हैं। केके अरोरा पंजीयन विभाग में सीनियर सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे हैं। दरअसल, ईडी की टीम ने ग्वालियर के सीपी कॉलोनी में अरोरा के आवास पर रेड की है। टीम सीआरपीएफ के दस्ते के साथ सुबह 5:00 बजे अरोरा के आवास पर दबिश देने पहुंची। हालांकि जब टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो अरोरा दंपत्ति अपने घर में मौजूद नहीं थे। घर में मौजूद दो किराएदारों को टीम ने घर के अंदर ही रहने के निर्देश देकर कार्रवाई शुरू की। ईडी के अफसर घर मे मौजूद दस्तावेजों की छानबीन कर रहें है।

सौरभ के वकील के बयान ने मचाई अफरा-तफरी

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की अहम कड़ी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के वकील के एक बयान ने अफसरशाही और नेताओं में खलबली मचा दी है। सुरक्षा मिलने पर सौरभ के कई बड़े नामों का खुलासा करने का स्टेटमेंट सामने आते ही गड़बड़ी का हिस्सा रहे लोगों को नाम उजागर होने का डर सताने लगा है। सिंडिकेट की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां सौरभ से जुड़े लोगों को एक-एक कर जांच की जद में ले रही है। ग्वालियर में पूर्व सब रजिस्ट्रार और भोपाल में कैसर विशेषज्ञ डॉ श्याम अग्रवाल पर दबिश से इसकी पुष्टि हो रही हैं। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगला नंबर किसका होगा।

सौरभ केवल छोटा सा आरोपी

लोकायुक्त और फिर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद सौरभ की मां ने उसकी जान को खतरा बताया था। अब यही बात सौरभ के वकील सूर्यकांत बुझाड़े ने दोहराई है। सौरभ और उसके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि इस मामले में वो आरोपी हैं और जांच में मदद करना चाहते हैं। लेकिन, सहयोग तभी कर पाएंगे जब सुरक्षित महसूस करेंगे। अधिवक्ता ने कहा कि ये मामला हम जितना समझ रहे हैं, उससे कहीं बड़ा है। यह पुराना सिंडिकेट है। सौरभ तो केवल छोटा सा आरोपी है। उसके सिर पर केस मढ़ दिया गया है। बरामद रकम और सोना सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स व नेताओं का है।

अस्पताल में लगाई काली कमाई?

भ्रष्टाचार के जरिए कमाया काला धन सौरभ शर्मा ने जिन लोगों के जरिए निवेश किया, अब उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसकी शुरुआत ग्वालियर में पूर्व सब रजिस्ट्रार केके अरोरा और भोपाल में डॉ. श्याम अग्रवाल व सौरभ की मौसेरी बहन के निवास से की गई। अरोरा, सौरभ के रिश्तेदार विनय हासवानी का बिजनेस पार्टनर है। बताया जा रहा है जिस फार्म हाउस से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद किया गया था, वो हासवानी का ही था। इधर, भोपाल में डॉ. अग्रवाल के नवोदय कैंसर अस्पताल, इंद्रपुरी बी सेक्टर स्थित निवास समेत चार स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबिश दी थी। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई जारी रही। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सौरभ शर्मा की काली कमाई डॉ. अग्रवाल के एमपी नगर स्थित नवोदय कैंसर अस्पताल में लगाई जा रही थी। अस्पताल व घर से लेन-देन के कुछ दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं।

एम्स भोपाल में दुर्लभ एड्रेनल ब्लैडर ट्यूमर का सफल उपचार

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल ने दुर्लभ और जटिल यूरोलॉजिकल ट्यूमर के इलाज में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यूरोलॉजी विभाग ने पिछले एक साल में उन्नत लैप्रोस्कोपिक तकनीक (दूरबीन के ऑपरेशन) द्वारा 13 हार्मोन स्रावित एड्रेनल ट्यूमर का सफल इलाज किया, जो संस्थान की चिकित्सा देखभाल में नवीनता और सर्जिकल विशेषज्ञता को दर्शाता है। इनमें से 7 मरीजों में क्रियाशील हार्मोन स्रावित एड्रेनल ट्यूमर, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा और एल्डोस्टेरोनोमा का इलाज मिनिमल इनवेसिव लैप्रोस्कोपिक एड्रेनलेक्टॉमी के जरिए किया गया। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें एड्रेनल ग्रंथि (जो किडनी के ऊपर स्थित होती है) को हटाने के लिए लैप्रोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे चीरे लगाए जाते हैं, और एक लैप्रोस्कोप (एक लंबी पतली ट्यूब जिसमें कैमरा और रोशनी लगी होती है) का उपयोग करके सर्जन एड्रेनल ग्रंथि तक पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया में कम दर्द होता है और रिकवरी की संभावना जल्दी होती है।

जून 2023 से मई 2024 के बीच की गई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में रेट्रोपेरिटोनियल और ट्रांसपेरिटोनियल दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जो ट्यूमर के आकार, स्थान और हार्मोनल गतिविधि के हिसाब से तय किए गए थे। इन प्रक्रियाओं के नतीजे उल्लेखनीय रहे, जिसमें 43% मरीजों में एल्डोस्टेरोन स्रावित एडिनोमा और 57% में फियोक्रोमोसाइटोमा पाए गए। फियोक्रोमोसाइटोमा से प्रभावित सभी मरीजों में ऑपरेशन के बाद रक्तचाप सामान्य हो गए। रेट्रोपेरिटोनियल मामलों के लिए औसत ऑपरेशन का समय 120 मिनट और ट्रांसपेरिटोनियल मामलों के लिए 90 मिनट था।

इसके अलावा, एम्स भोपाल ने तीन दुर्लभ न्यूरोएंडोक्राइन ब्लैडर ट्यूमर का सफल इलाज किया, जो दुनिया भर में ब्लैडर कैंसर के सभी मामलों का 1% से भी कम होते हैं। इन मामलों की पहचान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर और पैरागैंग्लिओमा के रूप में की गई और इनका प्रबंधन उन्नत निदान तकनीकों, जैसे इमेजिंग, मेटाबोलिक जांच और हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से किया गया। यह कार्य दोहा में आयोजित प्रतिष्ठित अरब एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी सम्मेलन में डॉ. केतन मेहरा द्वारा प्रस्तुत किया गया और बाद में यूसीकॉन (USICON) 2025, चेन्नई में भी प्रस्तुत किया गया, जहां इसे वैश्विक चिकित्सा समुदाय में व्यापक सराहना मिली। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आगे भी अनुसंधान किए जा रहे हैं।

प्रो. सिंह ने कहा, "यह उपलब्धि यूरोलॉजी में हमारी निरंतर प्रगति को दर्शाती है। इन उन्नत लैप्रोस्कोपिक तकनीकों की सफलता हमारे मरीजों को विश्वस्तरीय देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।" यह उपलब्धि यूरोलॉजिकल ट्यूमर के प्रबंधन में उन्नत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विभाग की विशेषज्ञता का प्रमाण है, जो एम्स भोपाल को यूरोलॉजी में एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह कार्य यूरोलॉजी से डॉ. देवाशीष कौशल, डॉ. कुमार माथवन, डॉ. केतन मेहरा और डॉ. निकिता श्रीवास्तव तथा एंडोक्राइनोलॉजी से डॉ. अल्पेश गोयल और डॉ. राहुल गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया।

जगदलपुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए 35 पदों के सृजन की स्वीकृति

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। राज्य शासन द्वारा जल संसधान विभाग अंतर्गत जगदलपुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए 35 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी किया गया है जारी आदेश के तहत अधीक्षण कार्यालय जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता (सिविल) एवं यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी के एक-एक पद, कार्यपालन अभियंता (सिविल) के दो पद शामिल हैं। इसी प्रकार सहायक अभियंता (सिविल) के तीन पद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, मुख्य मानचित्रकार (सिविल) एवं मानचित्रकार (सिविल) के एक-एक पद, सहायक ग्रेड-1 के दो पद, सहायक मानचित्रकार (सिविल) के एक पद, सहायक ग्रेड-2 के 4 पद, सहायक ग्रेड-3 के पांच पद, स्टेनो टायपिस्ट के दो पद, वाहन चालक के तीन पद, भृत्य लेवल-1 के छह पद और चौकीदार एवं फर्राश के लिए एक-एक पद की स्वीकृति प्रदान की गई है।

गाडरवारा शासकीय अस्पताल की स्थिति चिंताजनक, ओपीडी खाली, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही है। 12 बजे तक ओपीडी पूरी तरह से खाली हो जाती है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में न तो ओपीडी चालू हुई और न ही संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। जब अस्पताल प्रबंधन से इस स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए मरीजों को इंतजार करने के लिए कहा। स्थानीय निवासियों और मरीजों का कहना है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और अपनी निजी क्लीनिक पर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक मरीज ने कहा, "हम यहां इलाज के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए मौजूद नहीं है। यह स्थिति बेहद निराशाजनक है।" स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अस्पताल में सभी आवश्यक सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर और उचित इलाज मिल सके। गाडरवारा शासकीय अस्पताल की इस स्थिति ने स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है और अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे करता है।

पुलिस अधीक्षक विदिशा ने थाना त्योंदा और हैदरगढ़ का किया औचक निरीक्षण

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी ने देर रात्रि में थाना त्योंदा ओर हैदरगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के विभिन्न पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया। पुलिस कर्मचारियों को सतर्क रहकर गश्त करने और थाना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से बचने के निर्देश दिए गए। थाने के सभी रजिस्टरों को अपडेट रखने, मालखाने, हवालात आदि की नियमित जांच करने और थाने की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। गुंडा-बदमाशों पर नजररू थाना क्षेत्र के गुंडा- बदमाशों पर कड़ी नजर रखने और महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की शिकायतों पर

संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से सुना गया और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने निरीक्षण के दौरान थाना पुलिस को आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित किया।

तीन दिवसीय फैकल्टी एवं स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. इटारसी। शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी में स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ट के अंतर्गत तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम (एसडीपी) का आयोजन किया गया। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एम.पी. और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख अमित चक्रवर्ती (पीआईबीएम) और कु. दीया सिंघल ने संकायों को नए कौशल सेट और दक्षताओं का प्रशिक्षण दिया, जो वर्तमान उद्योग की जरूरतों के मानकों के अनुसार छात्रों को शिक्षण सिखाने में प्रासंगिक हैं। उन्होंने छात्रों को मनोसामाजिक कौशल सिखाया जिन्हें छात्रों के मौजूदा कौशल और कंपनियों द्वारा आवश्यक कौशल के बीच अंतर को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.एस. मेहरा ने नए मिश्रित शिक्षण सीखने के अनुभवों को भी स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ट प्रभारी स्नेहांशु सिंह ने पी.आई. बी.एम. टीम से निकट भविष्य में कॉलेज में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करने का अनुरोध किया। आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी डॉ. हरप्रीत रंधावा ने विद्यार्थियों को जीवन में भविष्य में नए प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी। डॉ. संजय आर्य ने कहा की इस प्रकार के प्रोग्राम से छात्रों में रोजगार, आलोचनात्मक स्वेच, सहयोग, उद्योग जगत, रचनात्मकता और संचार कौशल विकसित होता हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम (एसडीपी) में 50 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम में श्रीमती मंजरी अवस्थी, डॉ. हरप्रीत रंधावा, स्नेहांशु सिंह, रवींद्र चौरसिया, श्रीमती पुनम साहू, डॉ. हर्षा शर्मा, डॉ. संजय आर्य, डॉ. शिखा गुप्ता, डॉ. गिरीष परसाई, डॉ. श्रद्धा जैन, डॉ. नेहा सिकरवार, प्रिया कलोसिया, हेमंत गोहिया, क्षमा वर्मा, करिश्मा कश्यप, शोभा मीना, तरूणा तिवारी और मंथन दुबे ने तीन दिवसीय फैकल्टी विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में भाग लिया।

महिला को बातों में लगाकर दिन दहाड़े लूट ली सोने की चेन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. ताल्हर। जैन मंदिर से शांति धारा देखकर घर आ रही एक महिला को लुटेरों ने ऐसा चकमा दिया कि उक्त महिला को अपनी डेढ़ तोला सोने की चेन से हाथ धोना पड़ गया। घटना कोतवाली थाना अंतर्गत कटरा बाजार की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। लूट की घटना सीसी टीवी कैमरों में कैद हो गई है। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत कटरा पुलिस चौकी के सामने अतिशय आइसक्रीम गोदरे परिवार की एक महिला के साथ दो लोगों ने लूट कर ली। महिला जैन मंदिर से शांति धारा देखकर घर आ रही थी। रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति मिले और कहा कि ये चेन भीतर रख लो कुछ दिक्कत हो जाएगी। और फिर शातिर लुटेरे बातों में लगाकर चेन लूटकर भीतर बाजार से फरार हो गए। चेन करीब डेढ़ से दो तोला के बीच थी। घटना के संदर्भ में कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। चेन लूटने का पूरा घटनाक्रम कटरा बाजार में लगे विभिन्न सीसी टीवी कैमरों में कैद हो गया है जिसके आधार पर पुलिस संदिग्ध आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

सुशासन का साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

धान खरीदी का महापर्व

प्रति क्विंटल ₹3100

धान खरीदी

प्रति एकड़ 21 क्विंटल

- किसानों को खरीदी केंद्रों पर तत्काल 10 हजार का भुगतान
- 72 घंटों के भीतर धान मूल्य का पूर्ण भुगतान

RO No : 13090/1

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

Visit us : ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | DPRChhattisgarh | www.dprog.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)